CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

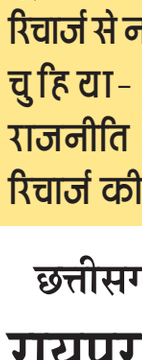
# हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 293 □ रायपुर, बुधवार 18 नवम्बर 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

## ब्रेकिंग न्यूज

### नेपाल प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह ने अपनी पहली भारत यात्रा में की कटौती, 3 दिन की बजाए सिर्फ 25 घंटे का रहेगा दौरा

**नई दिल्ली, 18 नवम्बर (न्यूज चैनल)।** नेपाल के प्रधानमंत्री बालेनद्र शाह ने अपनी पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा को छोटा कर दिया है। अब यह 3 दिन की बजाय सिर्फ 25 घंटे की होगी। काठमांडू, नई दिल्ली से बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास के लिए 2 अरब डॉलर (लगभग 18,000 करोड़ रुपये) के वित्तीय पैकेज की मांग करने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे बालेनद्र शाह 22 नवंबर की दोपहर को नई दिल्ली पहुंचेंगे और 23 नवंबर की शाम को काठमांडू लौट जाएंगे। नए कार्यक्रम के अनुसार, उनकी सभी गतिविधियां राष्ट्रीय राजधानी (नई दिल्ली) तक ही सीमित रहेंगी। पहले की योजना के अनुसार उन्हें बेंगलुरु, अहमदाबाद और उत्तराखंड भी जाना था, लेकिन अब वे वहां नहीं जाएंगे। इस यात्रा में प्रस्तावित वित्तीय पैकेज मुख्य मुद्दा हो सकता है। नेपाल 1 अरब डॉलर का रियायती कर्ज, 500 मिलियन डॉलर की ग्रांट (अनुदान) और 26 अगस्त को आई विनाशकारी बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण कार्यों के लिए 500 मिलियन डॉलर की मांग कर रहा है।



## बिरादरी की बातें

**चूहा- सुनती हो, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छोटा रिचार्ज से नहीं संभल रहा है राज्य**

**चुहिया- हां जी, लेकिन राजनीति में छोटे-बड़े किसी रिचार्ज की गारंटी नहीं होती..!**

## कैबिनेट बैठक में 4 अहम फैसले

# पंचायतों के माध्यम से शुद्ध पेयजल, अबूझमाड़िया छात्रों को बेहतर शिक्षा अवसर व राजनांदगांव को बड़ी सौगात



**रायपुर, 18 नवम्बर (हाईवे चैनल)।** मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सिविल लाइन स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 4 अहम फैसले लिए गए। मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन का प्रस्ताव को मंजूरी दी। राजनांदगांव जिले में ही बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

बैठक में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद ने ''छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026'' के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके अंतर्गत पूर्व में लागू वर्ष 2024 के नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।

नवीन नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित होगा। विशेष रूप से एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' के माध्यम से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा।

वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा लगातार दो वर्षों तक शत-प्रतिशत मीटरिंग सुनिश्चित करने वाली ग्राम पंचायतों को एकमुश्त 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा सकेगी। राज्य सरकार के इस निर्णय से छोटी ग्राम पंचायतों पर न केवल आर्थिक भार कम होगा, साथ ही ग्रामीण परिवारों को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

मंत्रिपरिषद द्वारा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदण्डों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। इस निर्णय से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी तथा उनके शैक्षणिक एवं सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर अर्थात 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी। नवीन सम्प्रेक्षण गृह के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा एवं पुनर्वास की सुविधाओं को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी।

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए भूमि आबंटन का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मण्डल को आबंटित की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल के संभागीय कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शैक्षणिक संस्थाओं को मण्डल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

## 10 मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर्स का आज से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू

### मुख्यमंत्री निवास घेरने की चेतावनी



**रायपुर, 18 नवम्बर (हाईवे चैनल)।** छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं. नियमितीकरण, ग्रेड पे सहित 9 विभिन्न मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स आज 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सभी 10 मेडिकल कॉलेज परिसर में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक प्रदर्शन किया जाएगा. इस हड़ताल में चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम करने वाली नियमित, संविदा और डेली वेजेस स्टाफ नर्सेज हड़ताल में शामिल होंगे।

नर्सिंग ऑफिसर्स की प्रमुख मांगों में 2018 में गठित कमेटी की रिपोर्ट को लागू करना, संविदा स्टॉफ, डेली वेजेस स्टॉफ और NHM स्टॉफ की नियमितीकरण की मांग शामिल है. साथ ही वेतन वृद्धि सहित अन्य सेवाओं से संबंधित मांगों को लेकर हड़ताल किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री एंव आयुक्त चिकित्सा शिक्षा कार्यालय में रायपुर और राजनांदगांव के पदाधिकारियों ने आंदोलन की आधिकारिक तौर पर जानकारी दे दी है। नर्सिंग ऑफिसर्स ने चेतावनी दी है कि आंदोलन के 2 से 3 दिनों में ग्रेड पे को लेकर आदेश जारी नहीं होता है, तो आंदोलन तेज कर किया जाएगा. प्रदेशभर के नर्सिंग संवर्ग एकजुट होकर 21 नवंबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव के लिए नवा रायपुर के प्रदर्शनस्थल पर एकजुट होंगे।

## साय सरकार का दावाः पटवारियों की हड़ताल बेअसर, निर्बाध जारी है धान खरीदी

**रायपुर, 18 नवम्बर (हाईवे चैनल)।** छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल के बावजूद समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का काम निर्बाध रूप से जारी है. शासन का कहना है कि चाक-चौबंद प्रशासनिक व्यवस्था के चलते किसानों को अपना धान बेचने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है. धान खरीदी के शुरुआती दो दिनों में ही राज्य के किसानों से 7 लाख 62 हजार क्विंटल से ज्यादा धान की खरीदी की जा चुकी है। गौरतलब है कि राज्य में धान खरीदी का सीजन शुरू होने से पहले ही पटवारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं. शासन का मानना है कि पटवारियों ने धान खरीदी जैसे संवेदनशील मुद्दे को आधार बनाकर अपनी अनुचित मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति अपनाई है. पटवारियों की हड़ताल का धान खरीदी पर कोई असर नहीं पड़ा है।

### छत्तीसगढ़ में एक्शन मोड में आईटी विभाग

## रायपुर, रायगढ़ समेत 5 जिलों में 16 टीमों ने एक साथ मारी रेड





**रायपुर/रायगढ़, 18 नवम्बर (हाईवे चैनल)।** छत्तीसगढ़ में बुधवार सुबह से आयकर विभाग एक्शन मोड में आ गया है. रायपुर, रायगढ़ समेत कई जिलों में आईटी विभाग की अलग-अलग टीमों ने छापा मारा है. बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कर चोरी की सूचना के आधार पर की जा रही है. ठिकानों पर अधिकारी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, आयकर विभाग के अधिकारियों ने इस कार्रवाई के लिए 16 अलग-अलग टीमें तैयार की थी. इन टीमों ने तड़के सुबह एक साथ रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़ और जांजगीर-चांपा में अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की। रायगढ़ में बर्बरीक कंपनी, सन स्टील और रायगढ़ इस्पात के दफ्तर, उसके मालिकों के घर समेत 3-4 ठिकानें आईटी विभाग की रडार पर आए हैं. रायगढ़ इस्पात के मालिक श्रवण अग्रवाल और कमल अग्रवाल के घर के अलावा दफ्तर और उद्योग में छापा पड़ा है. इन सभी ठिकानों पर एक साथ दबिश देकर आयकर विभाग की टीमें सुबह 5 बजे से टैक्स से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर रही हैं।

राजधानी रायपुर में भी कई जगहों पर आईटी विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई सामने आई है. चंदखुरी स्थित बहनाकाड़ी गाँव के एक फेक्ट्री में दबिश दी गई है. वहीं तेलीबांधा रिंग रोड-1 स्थित पीआरए ग्रुप के ऑफिस में छापा पड़ा रहा है. इसके अलावा रिंग रोड, शंकर नगर और खम्हारडीह इलाके में भी छापेमारी की खबर है। प्रदेश के पांच जिलों में एक साथ हुई इस कार्रवाई से कारोबारियों और औद्योगिक जगत में हलचल मची हुई है. फिलहाल इन कार्रवाइयों को लेकर विभाग की ओर से आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है. माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं. फिलहाल सभी की नजर आयकर विभाग की इस कार्रवाई और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों पर टिकी हुई है।

## जेल ब्रेक के बाद महासमुंद जेल में अब कैदी की मौत



**महासमुंद, 18 नवम्बर (हाईवे चैनल)।** इन दिनों महासमुंद जेल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। पहले जेल प्रशासन की लापरवाही और व्यवस्था की खामियों का फायदा उठाकर चार विचाराधीन बंदी जेल की उंची दीवार फांदकर फरार होने में कामयाब हो गये और अब जेल में बंदी एक की मौत का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार एन डीपीएस एक्ट के आरोप में बंदी तिफरा स्थित यदु नंदर नगर बिलासपुर निवासी सैय्यद अशफाक पिता सैय्यद युसुफ (44) जो 2023 से जिला जेल में बंदी था। आज करीब सात बजे अचानक तबियत खराब हो गयी और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जिसे एबुलेंस की मदद से मेडिकल कालेज लाया गया। जहाँ आकस्मिक चिकित्सा विभाग में चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान बंदी अचेत और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। उनकी आंखों की पुतलियां फैली हुई थीं और प्रकाश के प्रति प्रतिक्रिया नहीं थी। कॉर्नियल रिफ्लेक्स तथा जांघ की नाड़ी भी अनुपस्थित थी। ईसीजी जांच में हृदय की गतिविधि नहीं मिली। इसके बाद चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद उसके परिजनों को इसकी सूचना दी गयी। चिकित्सकों ने प्रथम दृष्टया बंदी की मौत आर्ट अटैक से होने की आंशका जता रहे है। फिलहाल पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा।

## टाइगर रिजर्व में लंगूर के अवैध शिकार मामले में ओडिशा के 7 आरोपी गिरफ्तार, जेल दाखिल





**धमतरी, 18 नवम्बर (हाईवे चैनल)।** उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व के वन्यप्राणी शिकार मामले में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल सात आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। वन्यप्राणी संरक्षण को लेकर विभाग की इस कार्रवाई में पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि फरार चल रहे अन्य चार आरोपियों को भी रेंजर की टीम ने दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया। वन विभाग के अनुसार, वन परिक्षेत्र तौरेंगा के अंतर्गत आने वाले गरीबा परिसर के आरक्षित वनखंड, कक्ष क्रमांक 1200 में वन्यप्राणी बंदर (मादा) के अवैध शिकार की घटना सामने आई थी। मामले में वन विभाग की संयुक्त टीम ने जांच एवं कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान की और उनके विरुद्ध वन अपराध दर्ज किया।

कार्रवाई के दौरान शिकार से संबंधित सामग्री भी जब्त की गई, जिसमें एक कुल्हाड़ी, छह छुरी, एक अन्य सामग्री, चार पीले थैले तथा एक मोटरसाइकिल शामिल है। मामले में तीन आरोपियों को 26 अक्टूबर को गिरफ्तार कर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था। इसके बाद फरार चल रहे अन्य सह-आरोपियों की तलाश जारी थी। विभाग की टीम ने आगे कार्रवाई करते हुए शेष चार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया और 17 नवंबर 2026 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, गरियाबंद के समक्ष प्रस्तुत कर जेल दाखिल कराया। गिरफ्तार आरोपियों में मुन्ना पिता लालधर संता, 50 वर्ष, बनमाली संता पिता मुकिया संता, 51 वर्ष, सोलनदर पिता रतन संता, 26 वर्ष, लालू संता पिता सुंदरक संता, 54 वर्ष, किशोर उर्फ केशर पिता राजना संता, 34 वर्ष,राजू उर्फ राजू संता पिता संघर संता, 38 वर्ष,केशु उर्फ बांधे संता पिता अरुण संता, 37 वर्ष सभी आरोपी ग्राम कटापानी, ग्राम पंचायत मुंगबेडा, पोस्ट गोना, थाना एवं तहसील रायघर, जिला नवरंगपुर (ओडिशा) के निवासी बताए गए हैं।

## शोएब ढेबर की गिरफ्तारी से पहले लीक हुई थी सूचना, इंस्पेक्टर विनीत दुबे सस्पेंड

**रायपुर, 18 नवम्बर (हाईवे चैनल)।** कांग्रेस नेता से 25 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी शोएब ढेबर फरार चल रहा है। रायपुर पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए जुटी हुई है। साथ ही उस पर कुल 15 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं अब मामले में शोएब की कथित मदद और गिरफ्तारी की गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। निरीक्षक विनीत दुबे को निलंबित कर दिया गया है। बस्तर आईजी बद्री नारायण मीणा ने निलंबन आदेश जारी किया है।




यह कार्रवाई रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला के 30 अक्टूबर को भेजे गए प्रतिवेदन के आधार पर की गई है। जानकारी के मुताबिक, तेलीबांधा थाने में दर्ज अपराध क्रमांक 403/2026 के मामले में निरीक्षक विनीत दुबे के संदिग्ध आचरण को निलंबन का आधार बनाया गया है। आरोप है कि फरार शोएब ढेबर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की ओर से बनाई गई योजना और गोपनीय जानकारी लीक हुई थी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने खम्हारडीह इलाके में शोएब ढेबर की गिरफ्तारी के लिए दबिश देने की योजना बनाई थी, लेकिन कार्रवाई से पहले ही आरोपी वहां से निकल गया। इसके बाद गोपनीय सूचना लीक होने को लेकर पुलिस विभाग में जांच शुरू हुई। इस मामले में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट के आरक्षक शिवम द्विवेदी और राहुल सिंह गौतम को भी पहले ही निलंबित किया जा चुका है।

## सड़क अधोसंरचना को मिल रही नई गति, धमतरी जिले में तेजी से आगे बढ़ रहे निर्माण व उन्नयन कार्य



**कुरमातराई-अरकार मार्ग पर बीटी सड़क निर्माण शुरू, कई मार्गों का डामरीकरण पूरा, 10 प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर भी चल रहा काम**

**धमतरी, 18 नवम्बर (हाईवे चैनल)।** धमतरी शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नई सड़कों के निर्माण, पुरानी सड़कों के नवीनीकरण, चौड़ीकरण एवं डामरीकरण के कार्यों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी कड़ी में कुरमातराई-अरकार मार्ग पर बीटी (बिटुमिनस टॉप) सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया है। जिले के अनेक अन्य मार्गों पर भी डामरीकरण एवं निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं, जबकि कई सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन पूरा किया जा चुका है। जिले में सड़क विकास के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने, आवागमन के पुराने मार्गों को बेहतर बनाने और यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए आवश्यकतानुसार सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। धमतरी शहर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क चौड़ीकरण, टू-लेन एवं फोर-लेन सड़क निर्माण की परियोजनाओं को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ ही पुल-पुलियों के निर्माण एवं उन्नयन से संबंधित कार्य भी किए जा रहे हैं।

फोर-लेन एवं अन्य प्रमुख सड़क परियोजनाओं पर कार्य जारी

जिले में सड़क अधोसंरचना को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इनमें सिहावा चौक से कोलियारी तक 5 किलोमीटर लंबाई की फोर-लेन सड़क का निर्माण प्रगतिरत है। इसी तरह मुजगहन से रब्राबांधा चौक तक फोर-लेन सड़क निर्माण का कार्य भी जारी है। आमदी नगर पंचायत क्षेत्र में 3.50 किलोमीटर फोर-लेन सड़क निर्माण की निविदा प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार अंबेडकर चौक से गंगरेल तक 11.50 किलोमीटर लंबाई की फोर-लेन एवं टू-लेन सड़क परियोजना भी निविदा प्रक्रिया में है। इसके अलावा कुरुद-चर्रा-छाती-उड़ेना-झिरिया-कुण्डेल-भोथली-बोंडरा-संबलपुर मार्ग के लगभग 16 किलोमीटर निर्माण की परियोजना भी शामिल है। धमतरी से बागतराई मार्ग के 2.80 किलोमीटर तथा छाती-गागरा-कंडेल-देवपुर मार्ग के निर्माण की निविदा प्रक्रिया जारी है। इसी क्रम में गुजरा से रीवागहन मार्ग के 2.80 किलोमीटर, देमार से बरसी मार्ग के 4.90 किलोमीटर तथा सिविल लाइन कॉलोनी से धमतरी पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य प्रगतिरत हैं।

**गुणवत्ता और समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने पर जोर:** कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में बेहतर सड़क अधोसंरचना का विकास प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। सड़कें केवल आवागमन का माध्यम नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण आधार भी हैं। उन्होंने कहा कि जिले में स्वीकृत एवं प्रगतिरत सड़क निर्माण, चौड़ीकरण, डामरीकरण तथा पुल-पुलियों के कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराने के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

## भारतीय शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2027 की 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारिणी की घोषित

- 10वीं की परीक्षा 8 से 20 मार्च और 12वीं की परीक्षा 8 से 30 मार्च तक होगी आयोजित
- छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित होंगी भारतीय शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी परीक्षाएं, संबद्ध विद्यालयों को ही बनाया जाएगा परीक्षा केंद्र

**रायपुर, 18 नवम्बर (हाईवे चैनल)।** भारतीय शिक्षा बोर्ड (केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की हाईस्कूल (कक्षा 10वीं) एवं हायर सेकेंडरी (कक्षा 12वीं) की वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारिणी घोषित कर दी है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार, ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल परीक्षा (कक्षा 10वीं) का आयोजन 8 मार्च 2027 से प्रारंभ होकर 20 मार्च 2027 तक किया जाएगा। वहीं, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल परीक्षा (कक्षा 12वीं) 8 मार्च 2027 से शुरू होकर 30 मार्च 2027 तक आयोजित होगी। बोर्ड द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, कक्षा 10वीं एवं 12वीं दोनों में संस्कृत अनिवार्य विषय के रूप में शामिल है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में भारतीय शिक्षा बोर्ड से 3 हाईस्कूल, 3 हायर सेकेंडरी स्कूल तथा 10 प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय संबद्ध हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार भारतीय शिक्षा बोर्ड की हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्तर की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। परीक्षा की व्यवस्था के तहत बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इससे संबंधित विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए अन्य स्थानों पर नहीं जाना होगा और वे अपने संबद्ध विद्यालयों में ही परीक्षा दे सकेंगे।

CMYK